इंडस मोबाइल वितरण प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

डेटाविंड इन्नोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ओआरएस।

(सिविल अपील सं. 5370-71, 2017)

अप्रैल 19,2017

[पिनाकी चंद्र घोस और आर. एफ. नरीमन, जे. जे]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996- धारा 20- मध्यस्थता कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए मुंबई में अधिकारिता-मध्यस्थता का स्थान निर्धारित किया गया। क्या किसी समझौते में अनन्य क्षेत्राधिकार खंड है जिसमें कहा गया है कि समझौते के तहत पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद के संबंध में अकेले मुंबई की अदालतों के पास क्षेत्राधिकार होगा, अन्य सभी अदालतों को बाहर कर देगा - माना गया। एक बार मध्यस्थता की सीट तय हो गई है, यह उन अदालतों के लिए एक विशेष क्षेत्राधिकार खंड की प्रकृति में होगा जो मध्यस्थता पर पर्यवेक्षी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। उपचार के लिए कोई भी दावा केवल मध्यस्थता की सीट के रूप में नामित स्थान की अदालतों में किए जाने पर सहमति है। -तथ्यों पर, क्षण "सीट" निर्धारित की जाती है, तथ्य यह है कि सीट मुंबई में है, के बीच समझौते से उत्पन्न होने वाली मध्यस्थता कार्यवाही को

विनियमित करने के उद्देश्य से मुंबई की अदालतों को विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा। पक्षकार-क्षेत्राधिकार।

शब्द और वाक्यांश-स्थान, न्यायिक सीट, स्थल, सीट -मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 20 के संदर्भ में चर्चा की गई।

न्यायालय द्वारा अपीलों का निस्तारण करते हुए अभिनिर्धारित किया गया :-

1. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के सभी प्रासंगिक प्रावधानों का एक पहलू यह दर्शाता है कि जिस क्षण सीट नामित की जाती है, यह एक विशेष क्षेत्राधिकार खंड के समान है। वर्तमान मामले के तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता की सीट मुंबई है और खंड 19 यह स्पष्ट करता है कि न्यायक्षेत्र विशेष रूप से मुंबई की अदालतों में निहित है। मध्यस्थता कानून के तहत, सिविल प्रक्रिया संहिता के विपरीत, जो अदालतों में दायर मुकदमों पर लागू होता है, "सीट" का संदर्भ एक अवधारणा है जिसके द्वारा मध्यस्थता खंड के पक्षकारों द्वारा एक तटस्थ स्थान चुना जा सकता है। तटस्थ स्थल का शास्त्रीय अर्थ में अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है, यानी कार्रवाई के कारण का कोई हिस्सा नहीं हो सकता है। तटस्थ स्थान पर उत्पन्न हो सकता है और न ही सी. पी. सी. की धारा 16 से 21 के किसी भी प्रावधान को आकर्षित किया जाएगा। हालांकि मध्यस्थता कानून में, जिस क्षण "सीट" निर्धारित की जाती है, यह तथ्य

कि सीट मुंबई में है, पक्षों के बीच समझौते से उत्पन्न होने वाली मध्यस्थता कार्यवाही को विनियमित करने के उद्देश्यों के लिए मुंबई की अदालतों को विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान करेगी। [पैरा 20] [759-बी-डी]

भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम कैसर एल्यूमीनियम तकनीकी सर्विसेज इंक., (2012) 9 एससीसी 552: [2012] 12 एससीआर 327; एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड बनाम एनरकॉन जीएमबीएच (2014) 5 एससीसी 1: [2014] 2 एस. सी. आर. 855-पर निर्भर।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ (2014) 7 एससीसी 603 : [2014] 6 एस. सी. आर. 456; हार्मनी इनोवेशन शिपिंग लिमिटेड बनाम गुप्ता कोल इंडिया लिमिटेड और एक अन्य (2015) 9 एस. सी. सी. 172 [2015] 2 एस. सी. आर. 697; भारत संघ बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य (2015) 10 एस. सी. सी. 213 [2015] 10 एस. सी. आर. 85; एट्ज़ेन बल्क ए/एस बनाम आशापुरा माइनकेम लिमिटेड और अन्य (2016) 11 एस. सी. सी. 508: [2016] 2 एस. सी. आर. 634; स्वास्तिक गैस प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2013) 9 एससीसी 32: [2013] 7 एससीआर 581; बी. ई. सिमोइस वॉन स्टारबर्ग निडेन्थल और एक अन्य बनाम छत्तीसगढ़ निवेश लिमिटेड (2015) 12 एस. सी. सी. 225-संदर्भित।

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

[2012] 12 एससीआर 327	पर भरोसा	पैरा 10
[2014] 2 एससीआर 855	पर भरोसा	पैरा 13
[2014] 6 एससीआर 456	संदर्भित।	पैरा 15
[2015] 2 एससीआर 697	संदर्भित।	पैरा 15
[2015] 10 एससीआर 85	संदर्भित।	पैरा 15
[2016] 2 एससीआर 634	संदर्भित।	पैरा 16
[2013] 7 एससीआर 581	संदर्भित।	पैरा 21
(2015) 12 एससीसी 225	संदर्भित।	पैरा 21

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: की सिविल अपील सं. 5370-5371/2017

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली की मध्यस्थता याचिका संख्या 592/2015 और ओ.एम.पी.(आई) सं. 531/2015 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 03.06.2016 से।

के. एस. महादेवन, कृष्ण कुमार आर. एस., राजेश कुमार, अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए।

मोहित चौधरी, सुश्री पूजा शर्मा, कुणाल सचदेवा, इमरान अली, अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायधीश आर. एफ. नरीमन, जे. द्वारा पारित किया गया।

1. स्वीकृति दे दी गई।

2. वर्तमान अपीलें एक दिलचस्प सवाल उठाती हैं कि क्या, जब मध्यस्थता की सीट मुंबई है, तो एक विशेष क्षेत्राधिकार खंड जिसमें कहा गया है कि समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों के संबंध में अकेले मुंबई की अदालतों के पास क्षेत्राधिकार होगा, सहित अन्य सभी अदालतों को बाहर कर देगा। दिल्ली उच्च न्यायालय, जिसके फैसले के खिलाफ अपील की गई है।

3. विवाद को समझने के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रतिवादी नंबर 1 मोबाइल फोन, टैबलेट और उनके सहायक उपकरण के निर्माण, विपणन और वितरण में लगा हुआ है। प्रतिवादी नंबर 1 का पंजीकृत कार्यालय अमृतसर, पंजाब में है। प्रतिवादी नंबर 1 नई दिल्ली से चेन्नई में अपीलकर्ता को माल की आपूर्ति कर रहा था। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 1 से संपर्क किया और अपने रिटेल चेन पार्टनर के रूप में प्रतिवादी नंबर 1 के साथ व्यापार करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। यह मामला होने पर, पार्टियों के बीच दिनांक 25.10.2014 को एक समझौता किया गया था। खंड 18 और 19 हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, और यहां नीचे दिए गए हैं:

"विवाद समाधान तंत्रः

मध्यस्थताः इस समझौते के निर्माण, अर्थ, दायरे, संचालन या प्रभाव या इस समझौते के उल्लंघन के संबंध में पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद के मामले में, पार्टियों को ऐसे विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए अच्छे विश्वास में प्रयास करना होगा।

यदि इस तरह के विवाद या मतभेद को पार्टियों (विवाद) द्वारा इसके घटित होने के तीस दिनों के भीतर, या आपसी सहमति से इतने लंबे समय के भीतर सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जा सकता है, तो कोई भी पक्ष विवाद को पार्टियों के नामित वरिष्ठ अधिकारियों को संदर्भित कर सकता है।

यदि ऐसे अधिकारियों द्वारा विवाद को रेफरल की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर, या आपसी सहमति से इतने लंबे समय के भीतर सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे विवाद को अंततः मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत आयोजित मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाएगा। एकमात्र मध्यस्थ के संदर्भ में जिस पर पार्टियों द्वारा परस्पर सहमति व्यक्त की

जाएगी। ऐसी मध्यस्थता मुंबई में अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी।

मध्यस्थता पुरस्कार अंतिम होगा और उसके बाद के फैसले को पार्टियों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी भी न्यायालय में दर्ज किया जा सकता है या निर्णय की न्यायिक स्वीकृति और प्रवर्तन के आदेश के लिए ऐसी अदालत में आवेदन किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो। मध्यस्थ के पास समझौते के विशिष्ट निष्पादन का आदेश देने की शक्ति होगी। प्रत्येक पक्ष मध्यस्थता की अपनी लागत स्वयं वहन करेगा।

इसके द्वारा पार्टियों के बीच सहमति हुई है कि वे विवाद के लंबित रहने के दौरान इस समझौते के तहत अपने संबंधित दायित्वों का पालन करना जारी रखेंगे।

19. इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या इसके संबंध में किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद केवल मुंबई की अदालतों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।"

4. पार्टियों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अपीलकर्ता को दिनांक 25.9.2015 को एक नोटिस भेजा गया। नोटिस में कहा गया है कि अपीलकर्ता ब्याज सहित 5 करोड़ रुपये के बकाया का

भुगतान करने में चूक कर रहा है और उसे 7 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है। समझौते के खंड 18 को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा लागू किया गया था, और एक न्यायमूर्ति एचआर मल्होत्रा को पार्टियों के बीच एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 15.10.2015 को एक उत्तर द्वारा, अपीलकर्ता ने न्यायमूर्ति मल्होत्रा की नियुक्ति पर आपत्ति जताई और प्रतिवादी संख्या 1 से अपना नोटिस वापस लेने को कहा। दिनांक 16.10.2015 को एक और उत्तर द्वारा, नोटिस में दिए गए कथनों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया।

5. इसके बाद प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दो याचिकाएं दायर की गईं - पहली सितंबर 2015 को, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत मामले में विभिन्न अंतरिम राहत की मांग की गई। 22.9.2015 के एक आदेश द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम आवेदन में नोटिस जारी किया और अपीलकर्ता को संपत्ति संख्या 281, टीके रोड, अलवरपेट, चेन्नई -600018 के संबंध में किसी तीसरे पक्ष के हितों को स्थानांतरित करने, अलग करने या बनाने से रोक दिया। सुनवाई की अगली तारीख तक. दिनांक 28.10.2015 के एक आवेदन द्वारा, प्रतिवादी नंबर 1 ने एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए धारा 11 याचिका दायर की।

6. आक्षेपित निर्णय द्वारा दोनों आवेदनों का निराकरण किया गया। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आक्षेपित निर्णय में यह माना गया कि

चूंकि कार्रवाई के कारण का कोई भी हिस्सा मुंबई में उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए केवल तीन क्षेत्रों की अदालतों के पास इस मामले में क्षेत्राधिकार हो सकता है, अर्थात् दिल्ली और चेन्नई (जहां से और जहां माल की आपूर्ति की गई थी), और अमृतसर (जो अपीलकर्ता कंपनी का पंजीकृत कार्यालय है)। इसलिए अदालत ने माना कि विशेष क्षेत्राधिकार खंड तथ्यों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि मुंबई की अदालतों के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा। इसलिए, यह निर्धारित किया गया कि दिल्ली पहला न्यायालय है जिसके पास इस मामले में अधिकार क्षेत्र होगा और 22.9.2015 के अंतरिम आदेश की पुष्टि करने के लिए आगे बढ़ा और न्यायमूर्ति एसएन वरियावा, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को नियुक्त करके धारा 11 याचिका का निपटान करने के लिए आगे बढ़ा। कार्यवाही में एकमात्र मध्यस्थ के रूप में फैसले में दर्ज किया गया कि मध्यस्थता का संचालन मुंबई में होगा।

7. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि कार्रवाई का कोई भी कारण मुंबई में उत्पन्न नहीं हुआ, फिर भी मध्यस्थता की सीट मुंबई में है। मुंबई की अदालतों के पास सभी कार्यवाहियों में विशेष क्षेत्राधिकार होगा। उनके अनुसार, इसलिए, सुनाया गया फैसला गलत था और इसे रद्द करने की जरूरत है।

8. इन तर्कों के विरोध में, प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील ने यह कहते हुए फैसले का समर्थन करने की मांग की कि कार्रवाई के कारण का कोई भी हिस्सा मुंबई में उत्पन्न नहीं हुआ। यह मामला है, भले ही सीट मुंबई में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अदालत को अधिकार क्षेत्र देने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा निर्धारित परीक्षणों में से एक को कम से कम पूरा किया जाना चाहिए। इनमें से कोई भी परीक्षण वर्तमान मामले के तथ्यों पर खरा नहीं उतर रहा है, आक्षेपित निर्णय सही है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रासंगिक प्रावधान यहां नीचे दिए गए हैं:

> "2. परिभाषाएँ - (1) इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
>
> (ई) "न्यायालय" का अर्थ है किसी जिले में मूल क्षेत्राधिकार का प्रमुख सिविल न्यायालय, और इसमें अपने सामान्य मूल नागरिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय शामिल है, जिसके पास मध्यस्थता की विषय-वस्तु बनाने वाले प्रश्नों को तय करने का क्षेत्राधिकार है, यदि वही हो किसी मुकदमे का विषय रहा हो, लेकिन इसमें ऐसे प्रमुख

सिविल न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई भी सिविल न्यायालय, या लघु वाद न्यायालय शामिल नहीं है;

(2) यह भाग वहां लागू होगा जहां मध्यस्थता का स्थान भारत में है।

20. मध्यस्थता का स्थान- (1) पक्ष मध्यस्थता के स्थान पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी समझौते के विफल होने पर, मध्यस्थता का स्थान पार्टियों की सुविधा सहित मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के बावजूद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण, जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, गवाहों, विशेषज्ञों या सुनवाई के लिए अपने सदस्यों के बीच परामर्श के लिए किसी भी स्थान पर मिल सकती है। पार्टियों, या दस्तावेज़ों, वस्तुओं या अन्य संपत्ति के निरीक्षण के लिए।

31. मध्यस्थ निर्णय का स्वरूप और विषय-वस्तु –

(4) मध्यस्थ पुरस्कार में धारा 20 के अनुसार निर्धारित अपनी तिथि और मध्यस्थता का स्थान बताया जाएगा और निर्णय उस स्थान पर दिया गया माना जाएगा।"

10. न्यायिक सीट की अवधारणा इंग्लैंड की अदालतों द्वारा विकसित की गई है और अब यह हमारे न्यायशास्त्र में मजबूती से अंतर्निहित हो गई है। इस प्रकार, भारत एल्युमीनियम कंपनी बनाम कैसर एल्युमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक., (2012) 9 एससीसी 552 मामले में संविधान पीठ ने कुछ विस्तार से "सीट" का उल्लेख किया है। पैराग्राफ 96 शिक्षाप्रद है और इसमें बताया गया है:-

“मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2(1)(ई) इस प्रकार है:”

2. परिभाषाएँ.— (1) इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(ए)-(डी)***

(ई) 'न्यायालय' का अर्थ है किसी जिले में मूल क्षेत्राधिकार का प्रधान सिविल न्यायालय, और इसमें अपने सामान्य मूल नागरिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय भी शामिल है, जिसके पास मध्यस्थता की विषय-वस्तु बनाने वाले प्रश्नों को तय करने का अधिकार क्षेत्र है, यदि

ऐसा होता है किसी मुकदमे का विषय-वस्तु रहा है, लेकिन इसमें ऐसे प्रधान सिविल न्यायालय, या किसी लघु वाद न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई भी सिविल न्यायालय शामिल नहीं है;" हमारी राय है, "मध्यस्थता की विषय-वस्तु" शब्द को "मुकदमे की विषय-वस्तु" के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है। धारा 2(1)(ई) में "विषय-वस्तु" शब्द भाग। तक ही सीमित है। इसका विवाद समाधान की प्रक्रिया के साथ एक संदर्भ और संबंध है। इसका उद्देश्य मध्यस्थता कार्यवाही पर पर्यवेक्षी नियंत्रण रखने वाली अदालतों की पहचान करना है। इसलिए, यह एक अदालत को संदर्भित करता है जो अनिवार्य रूप से मध्यस्थता प्रक्रिया की सीट की अदालत होगी। हमारी राय में, धारा 2(1)(ई) के प्रावधान को धारा 20 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए जो पार्टी की स्वायत्तता को मान्यता देते हैं। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत संकीर्ण निर्माण को स्वीकार करना, वास्तव में, धारा 20 को निरर्थक बना देगा। हमारे विचार में, विधायिका ने जानबूझकर दो अदालतों को क्षेत्राधिकार दिया है यानी वह अदालत जिसका क्षेत्राधिकार होगा जहां कार्रवाई का कारण स्थित है और वह अदालतें जहां मध्यस्थता होती है। यह

आवश्यक था क्योंकि कई अवसरों पर समझौता ऐसी जगह पर मध्यस्थता की सीट प्रदान कर सकता है जो दोनों पक्षों के लिए तटस्थ होगी। इसलिए, जिन अदालतों में मध्यस्थता होती है, उन्हें मध्यस्थता प्रक्रिया पर पर्यवेक्षी नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, यदि मध्यस्थता दिल्ली में होती है, जहां कोई भी पक्ष दिल्ली से नहीं है, (मुंबई के एक पक्ष और कोलकाता के दूसरे पक्ष के बीच दिल्ली को एक तटस्थ स्थान के रूप में चुना गया है) और दिल्ली में बैठा न्यायाधिकरण एक अंतरिम पारित करता है मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 17 के तहत आदेश, धारा 37 के तहत ऐसे अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील दिल्ली की अदालतों में होनी चाहिए क्योंकि मध्यस्थता कार्यवाही और न्यायाधिकरण पर पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार वाली अदालतें हैं। यह इस तथ्य के बावजूद होगा कि अनुबंध के तहत निष्पादित दायित्वों को या तो मुंबई या कोलकाता में पूरा किया जाना था, और केवल मध्यस्थता दिल्ली में होनी थी। ऐसी परिस्थितियों में, दोनों अदालतों का क्षेत्राधिकार होगा यानी वह अदालत जिसके अधिकार क्षेत्र में मुकदमे की विषय-वस्तु स्थित है और वह अदालतें जिसके अधिकार क्षेत्र में विवाद समाधान यानी मध्यस्थता स्थित है।" [पैरा 96]

11. पैराग्राफ 98 से 100 में "सीट" के संबंध में कानून इस प्रकार निर्धारित किया गया है:

"अब हम धारा 20 पर आते हैं, जो इस प्रकार है:

"20. मध्यस्थता का स्थान.— (1) पार्टियां मध्यस्थता के स्थान पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी समझौते के विफल होने पर, मध्यस्थता का स्थान पार्टियों की सुविधा सहित मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के बावजूद, मध्यस्थता न्यायाधिकरण, जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, गवाहों, विशेषज्ञों या सुनवाई के लिए अपने सदस्यों के बीच परामर्श के लिए किसी भी स्थान पर मिल सकती है। पार्टियों, या दस्तावेज़ों, वस्तुओं या अन्य संपत्ति के निरीक्षण के लिए।" धारा 20 को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि मध्यस्थता का स्थान भारत में है, पक्षकार भारत के भीतर किसी भी "स्थान" या "सीट" पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे वह दिल्ली, मुंबई आदि हो। पार्टियों के समझौते के आधार

पर, धारा 20(2) ट्रिब्यूनल को ऐसी मध्यस्थता की जगह/सीट निर्धारित करने के लिए अधिकृत करती है। धारा 20(3) ट्रिब्यूनल को गवाहों, विशेषज्ञों या पक्षों की सुनवाई के लिए अपने सदस्यों के बीच परामर्श जैसे मामलों में सुविधा के स्थान पर सुनवाई करने के लिए किसी भी स्थान पर मिलने में सक्षम बनाती है।

सबसे सुविधाजनक "स्थल" के निर्धारण का ध्यान धारा 20(3) द्वारा रखा गया है । धारा 20 को धारा 2(2) के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए , जो भाग । की प्रयोज्यता पर एक प्रारंभिक सीमा लगाता है, जहां मध्यस्थता का स्थान भारत में है। इसलिए, धारा 20 भी भाग । की अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रयोज्यता को प्रस्तुत करने का समर्थन नहीं करेगी, जैसा कि अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रचारित किया गया है, जहां तक विशुद्ध घरेलू मध्यस्थता का संबंध है।

सच है, कि एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में, भारत में एक सीट होने पर, भारत के बाहर सुनवाई की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में, मध्यस्थता की सुनवाई पार्टियों द्वारा निर्धारित स्थान पर की जाएगी,

लेकिन इसका मध्यस्थता की सीट बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो भारत में ही रहेगी। इस संबंध में कानूनी स्थिति को रेडफर्न और हंटर, द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन (1986) द्वारा पृष्ठ पर संक्षेपित किया गया है। 69 निम्नलिखित परिच्छेद में "मध्यस्थता का स्थान" शीर्षक के अंतर्गत:

"पिछली चर्चा इस आधार पर रही है कि मध्यस्थता का केवल एक ही 'स्थान' है। यह पार्टियों द्वारा या उनकी ओर से चुनी गई जगह होगी; और इसे मध्यस्थता समझौते या संदर्भ की शर्तों या कार्यवाही के मिनटों में या किसी अन्य तरीके से मध्यस्थता के स्थान या 'सीट' के रूप में नामित किया जाएगा। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अपनी सभी बैठकें या सुनवाई मध्यस्थता के स्थान पर आयोजित करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में अक्सर कई अलग-अलग देशों के, कई अलग-अलग राष्ट्रीयताओं के लोग शामिल होते हैं। इन परिस्थितियों में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए मध्यस्थता के निर्दिष्ट स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर बैठकें आयोजित करना या यहां तक कि सुनवाई करना किसी भी तरह से असामान्य नहीं है, या तो अपनी सुविधा

के लिए या पार्टियों या उनके गवाहों की सुविधा के लिए...। एक देश में बैठे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए दूसरे देश में सुनवाई करना अधिक सुविधाजनक हो सकता है- उदाहरण के लिए, साक्ष्य लेने के उद्देश्य से... ऐसी परिस्थितियों में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण के प्रत्येक कदम का मतलब यह नहीं है कि मध्यस्थता की सीट बदल जाती है। मध्यस्थता की सीट वह स्थान बनी हुई है जिस पर शुरू में पार्टियों द्वारा या उनकी ओर से सहमति व्यक्त की गई थी।" यह, हमारे विचार में, व्यावहारिक विचारों और "सीट" [धारा 20(1) और 20(2)] और "स्थल" [धारा 20(3)] के बीच अंतर का सही चित्रण है। हम यहां बता सकते हैं कि "सीट" और "स्थान" के बीच का अंतर उस स्थिति में काफी महत्वपूर्ण होगा, मध्यस्थता समझौता एक विदेशी देश को मध्यस्थता की "सीट"/"स्थान" के रूप में नामित करता है और मध्यस्थता अधिनियम का भी चयन करता है, 1996 मध्यस्थता कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले क्यूरियल कानून/कानून के रूप में। यह तय करना व्यक्तिगत समझौते के निर्माण का मामला होगा कि:

(i) नामित विदेशी "सीट" को वास्तव में केवल "स्थल"/"स्थान" प्रदान करने के रूप में पढ़ा जाएगा जहां

सुनवाई होगी, मध्यस्थता अधिनियम , 1996 की पसंद को ध्यान में रखते हुए, क्यूरियल कानून के रूप में , या

(ii) एक विदेशी सीट का विशिष्ट पदनाम, आवश्यक रूप से उस देश के मध्यस्थता/क्यूरियल कानून की पसंद को अपने साथ लेकर, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के पक्षों द्वारा परस्पर विरोधी चयन विकल्प पर हावी होगा और इसमें शामिल होगा।" [पैरा 98-100]

12. एक शिक्षाप्रद अनुच्छेद में, इस न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थता की सीट के बारे में एक समझौता एक विशेष क्षेत्राधिकार खंड के अनुरूप है:

"इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता के संचालन का विनियमन और किसी पुरस्कार को चुनौती देना उस देश की अदालतों द्वारा किया जाना होगा जहां मध्यस्थता आयोजित की जा रही है। ऐसी अदालत तब पर्यवेक्षी अदालत होती है जिसके पास पुरस्कार रद्द करने की शक्ति होती है। यह जिनेवा कन्वेंशन और न्यूयॉर्क कन्वेंशन के साथ-साथ अनसिट्रल मॉडल कानून जैसे अंतरराष्ट्रीय उपकरणों की योजना को ध्यान में रखते हुए है। यह क्षेत्रीय सिद्धांत को भी मान्यता देता है जो किसी देश के राष्ट्रीय न्यायालयों के

माध्यम से अपने देश में निभाए जाने वाले न्यायिक कर्तव्य को विनियमित करने के संप्रभु अधिकार को प्रभावी बनाता है। एक तुलनात्मक उदाहरण के माध्यम से, हम सी वी. डी [2008 बस एलआर 843: 2007 ईडब्ल्यूसीए सीआईवी 1282 (सीए)] में अपील न्यायालय, इंग्लैंड द्वारा की गई टिप्पणियों को दोहरा सकते हैं, जिसमें यह देखा गया है कि:

"इससे यह पता चलता है कि मध्यस्थता के लिए सीट का विकल्प पुरस्कार पर हमला करने के इच्छुक उपचारों के लिए मंच का विकल्प होना चाहिए।" (जोर दिया गया)

उपरोक्त मामले में, अपील की अदालत ने ए बनाम बी [(2007) 1 ऑल ईआर (कॉम) 591: (2007) 1 लॉयड्स रिप 237] में की गई टिप्पणियों को मंजूरी दे दी थी, जिसमें यह देखा गया है कि:

"... मध्यस्थता की सीट के बारे में एक समझौता एक विशेष क्षेत्राधिकार खंड के अनुरूप है। मौजूदा अंतरिम या अंतिम पुरस्कार की वैधता के उपाय के लिए कोई भी दावा केवल मध्यस्थता की सीट के रूप में निर्दिष्ट स्थान की अदालतों में किए जाने पर सहमति है।" (जोर दिया गया) [पैरा 123]

13. संविधान पीठ के कानून के बयान को एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड बनाम एनरकॉन जीएमबीएच, (2014) 5 एससीसी 1 में और विस्तारित किया गया था। विभिन्न अंग्रेजी अधिकारियों को विस्तार से संदर्भित करने के बाद, इस न्यायालय ने संविधान पीठ का अनुसरण करते हुए कहा, निम्नलिखितानुसार:

> "अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से संबंधित कानून के अधिकांश विशेषज्ञों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि लगभग सभी राष्ट्रीय कानूनों में, मध्यस्थता मध्यस्थता की सीट/स्थान/स्थिति पर आधारित होती है। रेडफ़र्न और हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (5 वां संस्करण, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफ़ोर्ड/न्यूयॉर्क 2009), पैरा 3.54 में निष्कर्ष निकालते हैं कि "इस प्रकार मध्यस्थता की सीट इसके गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होने का इरादा है"। बाल्को में [भारत एल्युमीनियम कंपनी बनाम कैसर एल्युमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक., (2012) 9 एससीसी 552: (2012) 4 एससीसी (सिव) 810], यह आगे देखा गया है कि इसका मतलब यह नहीं है कि मध्यस्थता की सभी कार्यवाही मध्यस्थता की सीट पर आयोजित किया जाएगा. मध्यस्थ ऐसे स्थान पर बैठकें आयोजित करने के लिए स्वतंत्र हैं जो सभी संबंधितों के लिए सुविधाजनक हो। यह आवश्यक हो

सकता है क्योंकि मध्यस्थ अक्सर विभिन्न देशों से आते हैं। इसलिए, मध्यस्थता की सभी या कुछ बैठकें जहां मध्यस्थता की सीट स्थित है, उसके अलावा किसी अन्य स्थान पर आयोजित करना सुविधाजनक हो सकता है। बाल्को में, रेडफर्न और हंटर के प्रासंगिक अंश को उद्धृत किया गया है जो इस प्रकार है: (एससीसी पृष्ठ 598, पैरा 75) "75।... 'पिछली चर्चा इस आधार पर की गई है कि मध्यस्थता का केवल एक ही "स्थान" है। यह पार्टियों द्वारा या उनकी ओर से चुनी गई जगह होगी; और इसे मध्यस्थता समझौते या संदर्भ की शर्तों या कार्यवाही के मिनटों में या किसी अन्य तरीके से मध्यस्थता के स्थान या "सीट" के रूप में नामित किया जाएगा। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अपनी सभी बैठकें या सुनवाई मध्यस्थता के स्थान पर आयोजित करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में अक्सर कई अलग-अलग देशों के, कई अलग-अलग राष्ट्रीयताओं के लोग शामिल होते हैं। इन परिस्थितियों में,मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए मध्यस्थता के निर्दिष्ट स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर बैठकें आयोजित करना या यहां तक कि सुनवाई करना किसी भी तरह से असामान्य

नहीं है, या तो अपनी सुविधा के लिए या पार्टियों या उनके गवाहों की सुविधा के लिए...।एक देश में बैठे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए दूसरे देश में सुनवाई करना अधिक सुविधाजनक हो सकता है- उदाहरण के लिए, साक्ष्य लेने के उद्देश्य से...ऐसी परिस्थितियों में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के प्रत्येक कदम का मतलब यह नहीं है कि मध्यस्थता की सीट बदल जाती है। मध्यस्थता की सीट वह स्थान बनी रहती है जिस पर प्रारंभ में पार्टियों द्वारा या उनकी ओर से सहमति व्यक्त की गई थी।' (नेविएरा मामला [नेविएरा अमेज़ोनिका पेरुआना एसए बनाम कंपेनिया इंटरनैशनल डी सेगुरोस डेल पेरू, (1988) 1 लॉयड्स रिप 116 (सीए)], लॉयड्स रिप पी. 121)" (मूल में जोर) इन टिप्पणियों को यूनियन ऑफ में भी देखा गया है भारत बनाम मैकडॉनेल डगलस कॉर्पोरेशन। [(1993) 2 लॉयड प्रतिनिधि 48]" [पैरा 134]

14. इस न्यायालय ने दोहराया कि एक बार मध्यस्थता की सीट तय हो जाने के बाद, यह उन अदालतों के लिए एक विशेष क्षेत्राधिकार खंड की प्रकृति में होगा जो मध्यस्थता पर पर्यवेक्षी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। (देखें: पैराग्राफ 138)।

15. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2014) 7 एससीसी, 603 में, कानून का यह कथन कई पैराग्राफों में दोहराया गया था। यह निर्णय यह स्पष्ट करता है कि "न्यायिक सीट" मध्यस्थता के "कानूनी स्थान" के अलावा और कुछ नहीं है। यह माना गया कि चूंकि न्यायिक सीट या मध्यस्थता का कानूनी स्थान लंदन था, इसलिए भारतीय अधिनियम के भाग I को छोड़कर केवल अंग्रेजी अदालतों के पास मध्यस्थता पर अधिकार क्षेत्र होगा। (देखें: पैराग्राफ 36, 41, 45 से 60 और 76.1 और 76.2)। हार्मनी इनोवेशन शिपिंग लिमिटेड बनाम गुप्ता कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य, (2015) 9 एससीसी 172 (देखें: पैराग्राफ 45 और 48) में इस फैसले पर भरोसा किया गया और इसका पालन किया गया। भारत संघ बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य, (2015) 10 एससीसी 213 में, इस न्यायालय ने पहले के सभी निर्णयों का उल्लेख किया और माना कि ऐसे मामलों में जहां मध्यस्थता की सीट लंदन है, आवश्यक निहितार्थ से मध्यस्थता और सुलह का भाग। अधिनियम, 1996 को बाहर रखा गया है क्योंकि मध्यस्थता पर अदालतों का पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार "सीट" के साथ चला जाता है।

16. एटजेन बल्क ए/एस बनाम आशापुरा माइनकेम लिमिटेड और अन्य, (2016) 11 एससीसी 508 में हाल के फैसले में , उपरोक्त सभी अधिकारियों को संदर्भित किया गया और उनका पालन किया गया। उक्त निर्णय का पैराग्राफ 34 इस प्रकार है:

"वास्तव में मध्यस्थता की न्यायिक सीट का चयन मात्र ऐसे स्थान पर लागू होने वाले कानून को आकर्षित करता है। दूसरे शब्दों में, यह निर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं होगा कि मध्यस्थता कार्यवाही पर कौन सा कानून लागू होगा, क्योंकि विशेष देश का कानून आईपीएसओ ज्यूर पर लागू होगा। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पर रेडफ़र्न और हंटर के निम्नलिखित अंश में मुद्दे की निम्नलिखित व्याख्या शामिल है:

"कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि पार्टियों ने प्रक्रियात्मक कानून का चयन किया है जो किसी विशेष देश में मध्यस्थता प्रदान करके उनकी मध्यस्थता को नियंत्रित करेगा। यह बहुत अण्डाकार है और, हाल ही में डौने विंड फार्म के ब्रेस में आयोजित एक अंग्रेजी अदालत के रूप में यह हमेशा सच नहीं होता है। पार्टियों ने जो किया है वह किसी विशेष देश में मध्यस्थता का स्थान चुनना है। यह विकल्प अपने साथ उस देश के कानूनों के प्रति समर्पण लाता है, जिसमें मध्यस्थता पर उसके कानून के सभी अनिवार्य प्रावधान भी शामिल हैं। यह कहना कि पार्टियों ने मध्यस्थता को नियंत्रित करने के लिए उस विशेष कानून को "चुना" है, बल्कि यह कहने जैसा है कि एक अंग्रेज महिला

जो अपनी कार फ्रांस ले जाती है, उसने फ्रांसीसी यातायात कानून को "चुना" है, जो उसे दाहिनी ओर गाड़ी चलाने के लिए बाध्य करेगा। सड़क की सुरक्षा, दाहिनी ओर से आने वाले वाहनों को प्राथमिकता देना, और आम तौर पर यातायात कानूनों का पालन करना, जिनकी वह आदी नहीं हो सकती है। लेकिन यह कहना भाषा का अजीब प्रयोग होगा कि इस काल्पनिक मोटर चालक ने "फ्रांसीसी यातायात कानून" का विकल्प चुना था। उसने जो किया है वह फ्रांस जाने का विकल्प चुनना है। तब फ्रांसीसी कानून की प्रयोज्यता स्वतः ही लागू हो जाती है। यह पसंद का मामला नहीं है.

पार्टियाँ मध्यस्थता के किसी विशेष स्थान को ठीक से इसलिए चुन सकती हैं क्योंकि इसकी लेक्स आर्बिट्री वह है जो उन्हें आकर्षक लगती है। फिर भी, एक बार मध्यस्थता का स्थान चुन लेने के बाद, यह अपने साथ अपना कानून लेकर आता है। यदि उस कानून में ऐसे प्रावधान हैं जो मध्यस्थता के संबंध में अनिवार्य हैं, तो उन प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। यह किसी भी तरह की पसंद का मामला नहीं है, क्योंकि काल्पनिक मोटर चालक यह चुनने के लिए स्वतंत्र है कि कौन से स्थानीय यातायात कानूनों का

पालन करना है और किसकी अवहेलना करनी है।" [पैरा 34]

17. यह उल्लेख किया जा सकता है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 को विस्तृत विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2015 में संशोधित किया गया है। विधि आयोग ने विशेष रूप से "सीट" और "स्थल" के बीच अंतर को इस प्रकार बताया:

> “40. बाल्को मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधिनियम के भाग I और II एक-दूसरे से परस्पर अनन्य हैं। संसद की मंशा है कि अधिनियम प्रकृति में क्षेत्रीय है और धारा 9 और 34 केवल तभी लागू होंगे जब मध्यस्थता की सीट भारत में हो। यह सीट मध्यस्थता का "गुरुत्वाकर्षण का केंद्र" है, और यहां तक कि जहां दो विदेशी पक्ष भारत में मध्यस्थता करते हैं, भाग I लागू होगा और धारा 2(7) के 24 गुणों के अनुसार, पुरस्कार एक "घरेलू पुरस्कार" होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता की "सीट" को न्यायिक सीट के रूप में मान्यता दी; हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास के अनुरूप, यह देखा गया कि मध्यस्थता की सुनवाई मध्यस्थता की सीट के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी हो सकती है। इसलिए, "सीट" और "स्थल"

के बीच अंतर को मान्यता दी गई। ऐसे परिदृश्य में, यदि सीट भारत निर्धारित की जाती है, तो ही भाग । लागू होगा। यदि सीट विदेशी होती, तो भाग । अनुपयुक्त होता। भले ही भाग । को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया हो, "इसका मतलब केवल यह होगा कि पार्टियों ने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 से संविदात्मक रूप से आयात किया है, वे प्रावधान जो उनके मध्यस्थता के आंतरिक आचरण से संबंधित हैं और जो [विदेशी] के अनिवार्य प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं] प्रक्रियात्मक कानून/क्यूरियल कानून।" इसका उपयोग किसी भारतीय न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, बाल्को में निर्णय को स्पष्ट रूप से संभावित प्रभाव दिया गया था और निर्णय की तारीख के बाद निष्पादित मध्यस्थता समझौतों पर लागू किया गया था।

41. जबकि बाल्को में निर्णय सही दिशा में एक कदम है और इससे विदेशी मध्यस्थता में न्यायिक हस्तक्षेप काफी कम हो जाएगा, आयोग को लगता है कि अभी भी कुछ क्षेत्र हैं जो समस्याग्रस्त होने की संभावना है।

(i) जहां किसी पार्टी की संपत्ति भारत में स्थित है, और ऐसी संभावना है कि वह पार्टी निकट भविष्य में अपनी संपत्ति नष्ट कर देगी, तो दूसरे पक्ष के पास प्रभावी उपाय का अभाव होगा यदि मध्यस्थता की सीट विदेश में है। बाद वाले पक्ष के पास दो संभावित उपाय होंगे, लेकिन कोई भी प्रभावकारी नहीं होगा। सबसे पहले, बाद वाला पक्ष किसी विदेशी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण से अंतरिम आदेश प्राप्त कर सकता है और अंतरिम आदेश द्वारा बनाए गए अधिकार को लागू करने के लिए एक नागरिक मुकदमा दायर कर सकता है। अंतरिम आदेश सीधे निष्पादन याचिका दायर करके लागू नहीं किया जा सकेगा क्योंकि यह नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 13 और 44 ए (जो विदेशी निर्णयों को लागू करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है) के प्रयोजनों के लिए "निर्णय" या "डिक्री" के रूप में योग्य नहीं होगा।). दूसरे, यदि पूर्व पक्ष विदेशी आदेश की शर्तों का पालन नहीं करता है, तो बाद वाला पक्ष विदेशी न्यायालय में अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है और नागरिक संहिता की धारा 13 और 44 ए के तहत विदेशी न्यायालय के फैसले को लागू कर सकता है। प्रक्रिया। इनमें से कोई भी उपाय अपने द्वारा प्राप्त अंतरिम राहत को लागू

करने की मांग करने वाली पार्टी को 25 व्यावहारिक उपाय प्रदान करने की संभावना नहीं है।

ऐसा होने पर, यह एक स्पष्ट संभावना है कि एक विदेशी पार्टी अपने पक्ष में एक मध्यस्थ पुरस्कार प्राप्त करेगी, केवल यह महसूस करने के लिए कि जिस इकाई के खिलाफ उसे पुरस्कार लागू करना है, उसकी संपत्ति छीन ली गई है और उसे एक शेल कंपनी में बदल दिया गया है।

(ii) जबकि बाल्को में निर्णय को यह सुनिश्चित करने के लिए संभावित बनाया गया था कि गर्म बातचीत वाले सौदे रातोंरात पलट न जाएं, इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां अदालतें, यह जानने के बावजूद कि भाटिया में निर्णय अब अच्छा कानून नहीं है, जब भी वे इसे लागू करने के लिए मजबूर होते हैं बाल्को-पूर्व निष्पादित एक मध्यस्थता समझौते से उत्पन्न मामले का सामना करना पड़ रहा है।

42. उपरोक्त मुद्दों को धारा 2(2), 2(2ए), 20, 28 और 31 में प्रस्तावित संशोधनों के माध्यम से संबोधित किया गया है।"

18. अधिनियम में किए जाने वाले संशोधनों में, विधि आयोग ने निम्नलिखित की सिफारिश की:

“धारा 20 का संशोधन

12. धारा 20 में, "स्थान" शब्द को हटा दें और "मध्यस्थता" शब्दों से पहले "सीट और स्थान" शब्द जोड़ें।

(i) उप-धारा (1) में, "सहमत" शब्दों के बाद "स्थान" शब्द को हटा दें और "सीट और स्थान" शब्द जोड़ें।

(ii) उपधारा (3) में, शब्द "किसी भी स्थान पर मिलें" के बाद "स्थान" शब्द को हटा दें और "स्थान" शब्द जोड़ें।

[नोट: मध्यस्थता के कानूनी घर को दर्शाने के लिए, मध्यस्थता की "सीट" की अवधारणा के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के साथ अधिनियम के शब्दों को सुसंगत बनाने के लिए मध्यस्थता के मौजूदा वाक्यांश "स्थान" से विचलन का प्रस्ताव किया गया है। संशोधन आगे विधायी रूप से मध्यस्थता के "[कानूनी] सीट" से "[मात्र] स्थल" के बीच अंतर करता है।]

धारा 31 का संशोधन

17.धारा 31 में

(i) उपधारा (4) में, "इसकी तारीख और" शब्दों के बाद "स्थान" शब्द हटा दें और "सीट" शब्द जोड़ें।"

19. हालाँकि, संशोधित अधिनियम में उपरोक्त संशोधन शामिल नहीं हैं, संभवतः इसलिए क्योंकि बाल्को के फैसले ने बिना किसी अनिश्चित शब्दों के अधिनियम की धारा 2(2) के प्रयोजन के लिए "स्थान" को "न्यायिक सीट" के रूप में संदर्भित किया है। इसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि धारा 20(1) और 20 (2) जहां "स्थान" शब्द का उपयोग किया जाता है, वह "न्यायिक सीट" को संदर्भित करता है, जबकि धारा 20 (3) में, "स्थान" शब्द "स्थल" के बराबर है।" यह स्थापित कानून है, इसलिए इसे स्पष्ट रूप से शामिल करना अनावश्यक पाया गया कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अधिनियम के निर्माण के माध्यम से पहले ही क्या किया है।

20. उपरोक्त सभी प्रावधानों के एक पहलू से पता चलता है कि जिस क्षण सीट नामित की जाती है, यह एक विशेष क्षेत्राधिकार खंड के समान है। वर्तमान मामले के तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता की सीट मुंबई है और खंड 19 यह स्पष्ट करता है कि क्षेत्राधिकार विशेष रूप से मुंबई अदालतों में निहित है। मध्यस्थता कानून के तहत, नागरिक प्रक्रिया संहिता के विपरीत, जो अदालतों में दायर मुकदमों पर लागू होती है, "सीट" का संदर्भ एक अवधारणा है जिसके द्वारा मध्यस्थता खंड के

पक्षकारों द्वारा एक तटस्थ स्थान चुना जा सकता है। शास्त्रीय अर्थ में तटस्थ स्थल का क्षेत्राधिकार नहीं हो सकता है- यानी, तटस्थ स्थल पर कार्रवाई के कारण का कोई भी हिस्सा उत्पन्न नहीं हो सकता है और न ही सीपीसी की धारा 16 से 21 के किसी भी प्रावधान को आकर्षित किया जाएगा। हालाँकि, मध्यस्थता कानून में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, जिस क्षण "सीट" निर्धारित की जाती है, यह तथ्य कि सीट मुंबई में है, पार्टियों के बीच समझौते से उत्पन्न होने वाली मध्यस्थ कार्यवाही को विनियमित करने के प्रयोजनों के लिए मुंबई की अदालतों को विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान करेगी।

21. यह अच्छी तरह से तय है कि जहां एक से अधिक अदालतों का क्षेत्राधिकार है, वहां पार्टियों के लिए अन्य सभी अदालतों को बाहर करना खुला है। मामले के कानून के विस्तृत विश्लेषण के लिए, स्वास्तिक गैसेस प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (2013) 9 एससीसी 32 देखें। बी.ई. सिमोइस वॉन स्टारबर्ग निडेन्थल और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (2015) 12 एससीसी 225 के हालिया फैसले में इसका पालन किया गया था, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अकेले मुंबई अदालतों के पास देश की अन्य सभी अदालतों को बाहर करने का अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि मध्यस्थता की न्यायिक सीट मुंबई में है। यह मामला होने के कारण, आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है। आक्षेपित निर्णय द्वारा पुष्टि की गई निषेधाज्ञा इस निर्णय की

घोषणा की तारीख से चार सप्ताह की अवधि तक जारी रहेगी, ताकि उत्तरदाता मुंबई न्यायालय में धारा 9 के तहत आवश्यक कदम उठा सकें। तदनुसार अपीलों का निपटारा किया जाता है।

अपीलें निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती टविंकल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।